

संपादकीय

करारा जवाब

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने स्पष्ट किया कि वह युद्ध नहीं चाहता, पर जवाब देने को तैयार है। सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में नौ आतंकी ठिकाने तबाह किए।



भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिये पाकिस्तान में फल-फूल रहे आतंकवाद को सधा और करारा जवाब दिया है। भारतीय कार्रवाई सटीक, संतुलित और गैर-उकसावे वाली थी। इसमें भारतीय फौज ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इस ऑपरेशन के जरिये भारत ने फिर यह संदेश दिया है कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई उसकी तरफ आंख उठकर देखेगा तो उसे जवाब देने से भी नहीं हिचकेगा।

आतंकी कैप तबाह: भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में कुल नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन जगहों का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा और दूसरे आतंकी संगठन कर रहे थे। यहीं पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई, जिन्होंने भारत में कई कायराना वारदातों को अंजाम दिया। पाकिस्तान को बार-बार इनके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन कोई कदम उठाने के बजाय वह इनकी मौजूदगी को ही नकारता रहा। उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अपीलों पर भी ध्यान नहीं दिया बल्कि अब तो यह भी साफ है कि भारत पर और हमले करने की साजिश रची जा रही थी।

सबसे बड़ी कार्रवाई: 2016 और 2019 में भी भारतीय फौज ने आतंकवादी हमलों के जवाब में क्रमशः सर्जिकल स्ट्राइक और टेरर लॉन्च पैड को निशाना बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर 2019 की कार्रवाई से कहीं बड़ी है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं है। विडंबना यह है कि कई बार किसी एक पक्ष की द्वेषपूर्ण जिद की वजह से दूसरे को मजबूरन और आखिरी विकल्प के रूप में अपने बचाव में ठोस कदम उठाने पड़ते हैं।

जंग के मुहाने से लौटे भारत-पाकिस्तान, क्या संघर्ष विराम से शांति की उम्मीद

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से जिस तरह युद्ध के हालात बने हुए थे, उसमें यह आशंका गहरी हो रही थी कि कहीं यह ज्यादा जटिल शकल न अख्तियार कर ले। खासतौर पर पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि उसे भारत की ओर से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने से परेशानी है और इसी वजह से वह एक दिशाहीन टकराव की ओर बढ़ रहा है। मगर शनिवार को जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए सहमति बनने की खबर आई, उससे शांति के लिए एक सकारात्मक उम्मीद बंधी है।

पाकिस्तान ने शुरू से अपरिपक्वता का परिचय दिया
दरअसल, भारत की मंशा पहले भी सिर्फ इतनी ही रही कि उसने बेलगाम आतंकियों को सबक सिखाने के लिए एक 'नपी-तुली और नियंत्रित' प्रतिक्रिया का रास्ता अपनाया था, वह भी उन्हें काबू में करने के लगभग सारे विकल्प खत्म हो जाने के बाद। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने को अपने ऊपर हमला माना और जवाब में जिस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी, उसमें नाहक हड़बड़ी और अपरिपक्वता दिख रही थी। मगर इससे स्थिति बिगड़ जाने की आशंका खड़ी हो



गई थी। हालांकि इस बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव रखने वाले देशों के सामने समूची स्थिति स्पष्ट तौर पर रखी और इस संघर्ष में पाकिस्तान की भूमिका को भी रेखांकित किया। यह आतंकियों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई से लेकर कूटनीति के मोर्चे पर बहुस्तरीय घेरा था, जिसका दबाव पाकिस्तान साफ महसूस कर रहा था। शायद यही वजह है कि अमेरिकी मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी डीजीएमओ की ओर से भारत के डीजीएमओ को फोन आया और दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि

शनिवार को शाम पांच बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। जाहिर है, गंभीर शकल लेने की ओर बढ़ते टकराव के बीच पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम की घोषणा शांति की राह तलाशने के लिहाज से एक जरूरी पहलकदमी है और इस पर पाकिस्तान को पहले ही गौर करना चाहिए था। मगर कई बार किसी मसले को इस रूप में भी देखा जाता है कि अगर अंत में सब ठीक कर लिया गया तो वही रास्ता सही है। इसमें कोई दोराय नहीं कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं है। विडंबना यह है

कि कई बार किसी एक पक्ष की द्वेषपूर्ण जिद की वजह से दूसरे को मजबूरन और आखिरी विकल्प के रूप में अपने बचाव में ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के सामने यही विकल्प बचा था कि वह आतंकियों की लगातार ऐसी हरकतों को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई करे और उन्हें संरक्षण और शह देने वाले ठिकानों को निशाना बनाए। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने जो रवैया अपनाया हुआ था, उससे कई बार ऐसा लग भी रहा था कि वह नाहक ही हालात को उलझाने में लगा हुआ है।

अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत की संयमित प्रतिक्रिया के बदले में पाकिस्तान ने भारतीय इलाकों में न केवल बेलगाम गोलीबारी शुरू कर दी, बल्कि इस बात का भी खयाल नहीं रखा कि इसका शिकार आम नागरिक हो रहे हैं। एक ओर भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ थी, तो वहीं पाकिस्तान की गोलीबारी में पहले दिन दो बच्चों सहित कई लोगों की जान चली गई। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम ने पाकिस्तान के लिए एक मौका मुहैया कराया है कि वह आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने के रुख पर विचार करे और क्षेत्रीय शांति की दिशा में ठोस योगदान दे।

आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पैसे से आतंकवाद को पाल पोस रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान विगत तीन दशकों से भी अधिक समय से कर्ज के नाम पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थाओं से अरबों रुपए की राशि ले चुका है। बावजूद इसके न तो इस उसकी सूरत बदली न सीरत। आखिर इतनी बड़ी राशि कहां जाती है, यह किसी को नहीं मालूम। दूसरी ओर, आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या और उसके वित्त पोषण को लेकर उसका रवैया हमेशा ही सदिग्ध रहा है। विडंबना यह है कि जिस समय पहलगाम में पर्यटकों पर

आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की स्थिति बनी थी, वैसे समय में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को करीब बारह हजार करोड़ रुपए का नया ऋण दे दिया।

पाकिस्तान को लेकर भारत की चिंता स्वाभाविक है
इस नाजुक समय में आइएमएफ के इस फैसले पर भारत ने स्वाभाविक ही चिंता जताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान सीमा

पार आतंकवाद फैलाने के लिए करता है। पाकिस्तान में कृषि से लेकर अर्थव्यवस्था तक चौपट हो चुकी है। विकास की रोशनी दिखाई नहीं देती। एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से भी कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुस्त है। तब मुद्रा कोष को क्यों नहीं यह सवाल करना चाहिए कि उसका दिया पैसा आखिर किस मद में जाता है?

यह जगजाहिर है कि पाकिस्तान विकास की राह पर चलने के बजाय अपना सैन्य खर्च

लगातार बढ़ा रहा है। वहीं उसने सीमापार आतंकवाद फैलाने और अपने यहां आतंकवादियों को पालने-पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाले कर्ज की कोई कसौटी नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि मुद्रा कोष से मिली राशि का उपयोग पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने और आतंकवादियों को संरक्षण देने में नहीं करेगा।

ट्यापार

सीजफायर के बाद सरकार ने किया बड़ा ऐलान, रॉकेट बन गए ये शेयर, खरीदने की लूट

एयरआई का ऐलान

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने सोमवार को घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के मद्देनजर पिछले सप्ताह अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ान परिचालन फिर से शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति के कारण श्रीनगर और अमृतसर सहित उत्तर तथा पश्चिमी भारत के 32 हवाई अड्डों से नागरिक उड़ान परिचालन नौ मई से 15 मई तक निलंबित कर दिया गया था। सोमवार को एक बयान में, सरकारी स्वामित्व वाले एएआई ने कहा कि 32 हवाई अड्डे जो 15 मई को 05.29 बजे तक नागरिक विमान परिचालन के लिए बंद कर दिए गए थे।

एयर इंडिया ने क्या कहा?

हवाई अड्डों को फिर से खोलने के बारे में विमानन अधिकारियों की अधिसूचना के बाद, एयर इंडिया जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए उड़ानें शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। इस समय हम आपकी समझदारी की सराहना करते हैं, क्योंकि हमारी टीमें इन हवाई अड्डों पर परिचालन को सामान्य बनाने के लिए काम कर रही हैं। कृपया आगे की अपडेट के लिए बने रहें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे संपर्क केंद्र पर 011-693293833 / 011-69329999 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट <http://airindia.com> पर जाएं।

सुस्त पड़े शेयरों में आई जान, 20प्रतिशत उछला शेयर

एक तरफ शेयर बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ बिरला कॉर्पोरेशन के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत की उछल के बाद 1270 रुपये के लेवल पर बीएसई में पहुंच गया। कंपनी के शेयरों में उछल के पीछे की वजह तिमाही नतीजों को माना जा रहा है। कंपनी ने शेयर बाजारों के साथ मार्च तिमाही के प्रदर्शन को साझा किया है।

चौथी तिमाही में कितना हुआ प्रॉफिट?

बिरला कॉर्पोरेशन की तरफ से तरफ से दी जानकारी में बताया गया है कि बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में कुल नेट प्रॉफिट 257 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 33 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का रेवन्यू मार्च तिमाही में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2863 करोड़ रुपये रहा है। प्रति टन श्वद्धृद्ध 1014 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना

आधार पर 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। सीमेंट डिविजन का प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर हुआ है। चौथी तिमाही में बढ़कर 20 प्रतिशत पहुंच गया। जोकि एक साल पहले इसी तिमाही में 18.60 प्रतिशत था।

पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसा रहा प्रदर्शन

भले ही चौथी तिमाही में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया हो। लेकिन इसके बाद भी पूरे वित्त वर्ष में 295 करोड़ रुपये का प्रॉफिट ही बिरला कॉर्पोरेशन ने बनाया है। जोकि वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 30 प्रतिशत कम है। मार्च तिमाही के अंततक कंपनी के ऊपर कर्ज घटकर 2244 करोड़ रुपये रहा गया था। बीते 3 महीने के दौरान Birla Corporation के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक का भाव 14 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल में करीब 13 प्रतिशत टूटा है।

ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर सोमवार को 7प्रतिशत से अधिक उछलकर 500 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों 3 दिन में 37 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है।

ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों में लगातार तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। ड्रोन कंपनी के शेयर 3 दिन में 37 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को ब्रह्म में 7 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 500 रुपये पर पहुंच गए। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 864.10 रुपये है।

ड्रोन वाली कंपनी के शेयर 3 दिन में 37 प्रतिशत उछले, 500 रुपये पहुंच गया शेयर का दाम

वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 301 रुपये है। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप 2070 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

3 दिन में 37प्रतिशत से अधिक उछल गए ड्रोन कंपनी के शेयर

आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर पिछले तीन ट्रेडिंग सेशंस में 37 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। ड्रोन कंपनी के शेयर 7 मई 2025 को 359.20 रुपये पर बंद हुए थे।

समान अवधि में कंपनी को 10.3 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था।

672 रुपये था आईपीओ में शेयर का दाम

आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के आईपीओ में शेयर का दाम 672 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 26 जून 2023 को खुला था और यह 30 जून 2023 तक ओपन रहा। ड्रोन कंपनी के शेयर 7 जुलाई 2023 को बीएसई में 1305.10 रुपये पर लिस्ट हुए थे। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी का आईपीओ टोटल 106.06 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 85.2 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स कैटेगरी में 80.58 गुना दांव लगा था, जबकि क्रॉलीफाइंड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 125.81 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

5 साल में करीब 650 प्रतिशत चढ़ा भाव अब कंपनी के हाथ लगी बड़ी सफलता, 50 रुपये से कम भाव

राठी स्टील एंड पावर के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली। 50 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक का भाव बढ़ने की वजह एक सर्टिफिकेट मिलना है।

आज राठी स्टील एंड पावर के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली। 50 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक का भाव बढ़ने की वजह एक सर्टिफिकेट मिलना है। कंपनी ने बताया है कि उन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (ब्रह्म) से एक महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट मिला है। यह सर्टिफिकेट मिलना कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में बड़ी मदद करेगा।

बीएसई में सोमवार को कंपनी के शेयर 29.45 रुपये के लेवल पर खुले थे। लेकिन 9 प्रतिशत से अधिक की उछल के बाद ये बीएसई में 30.65 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। 2.27 मिनट पर स्टॉक 29.99 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा था।

52 वीक हाई से 60 प्रतिशत सस्ता हुआ है शेयर

इस तेजी के बाद भी राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड के शेयर अपने 52 वीक हाई 97.81 रुपये के लेवल से 60 प्रतिशत नीचे हैं। इस 52 वीक हाई के स्तर पर कंपनी के शेयर जुलाई 2024 में पहुंच गए थे। बता दें, राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड का 52 वकी लो लेवल 24.50 रुपये है।

5 साल में 650 प्रतिशत चढ़ा शेयर

यह साल कंपनी के निवेशकों के लिए काफी उतार और चढ़ाव भरा रहा है। मई में अबतक यह स्टॉक 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं, अप्रैल के महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 7.5 प्रतिशत गिरा था। हालांकि, इससे पहले मार्च के महीने में यह स्मॉल कैप स्टॉक 25 प्रतिशत चढ़ गया था। जिसकी वजह से 8 महीने से चले आ रहे गिरावट के दौर पर ब्रेक लग गया था। बता दें, बीते 5 साल में कंपनी ने पोर्जीशनल निवेशकों को करीब 650 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 2011 के बाद कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दिया है। आखिरी बार कंपनी की तरफ से 0.30 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। कंपनी का मार्केट कैप 255.19 करोड़ रुपये का है।

तीन-चार दिनों की लड़ाई में हमारी सेना ने दुश्मनों की हालात खस्ता की: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

- बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश में टॉप करने वाले बालाघाट के 17 विद्यार्थियों का सम्मान
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 169 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण भूमिपूजन



- देश की सीमा पर ही नहीं आंतरिक सुरक्षा में भी जवानों का साहस गौरवावित किया
- देश में अब हर मोर्चे पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा हैं
- प्रदेश में सबसे बड़ा पदोन्नति कार्यक्रम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आयोजित हुआ
- 64 सुरक्षा जवानों को मिली क्रम से पूर्व पदोन्नति

बालाघाट । राष्ट्रबाण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज हमारे देश की सीमा और अंतरिक सुरक्षा सबसे सुरक्षित हाथों में है, जिसका परिणाम दुनिया ने अभी-अभी ही देखा है। दुनिया ने देखा कि हमने 3 से 4 दिनों की लड़ाई में ही दुश्मनों के हालात खस्ता की है। देश की सीमा पर जो हुआ है वो सब हम देशवासियों के लिए बड़ा ही गौरवशाली क्षण रहा है। इसके अलावा बालाघाट में सुरक्षा जवानों ने भी आंतरिक सुरक्षा में जो कर दिखाया है वो प्रदेश का साहस बढ़ा रहा है। प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा जवानों का अदम्य साहस और वीरता दिखाई देती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हॉक फोर्स, सीआरपीएफ और जिला पुलिस का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक नक्सली बालाघाट की धरती पर ही मारे गए हैं। सीआरपीएफ, हॉक फोर्स और मप्र पुलिस जवानों के साहस के बल पर ही प्रदेश के 12 जिले जो नक्सल प्रभावित थे। आज बालाघाट मंडला और डिंडोरी में ही सीमित कर दिया है। इस बीच अभी भारत सरकार की रिपोर्ट में

खनिज का सम्राट है बालाघाट जिला - सीएम डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बालाघाट जिले कोई आम जिला नहीं है बल्कि यह तो खनिज का सम्राट है। यहाँ पर पीले सोने के रूप में मौजूद सुप्रसिद्ध तांबे की खदान, काले सोने के रूप में

मैंगनीज तथा तरल सोने के रूप में जल संपदा की भरपूर उपलब्धि मौजूद है। इसके साथ ही सफेद सोने के रूप बालाघाट का चिन्नीर चावल भी अब विश्व विख्यात होते जा रहा है।



लगभग 70 करोड़ की लागत से बनेगा आयुर्वेदिक कॉलेज

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बालाघाट में लगभग 70 करोड़ की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक कॉलेज समीक्षा भूमिपूजन कर दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ न केवल मरीजों का इलाज होगा बल्कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी अपनी पढ़ाई पूरी करके समाज सेवा के संकल्प लेंगे। यहाँ नर्सिंग, पैरामेडिकल व अन्य कोर्स भी सम्पन्न होंगे तथा युवाओं को चिकित्सा क्षेत्र में एक नया अवसर प्रदान होगा। आज की स्थिति में 50 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हैं, और बालाघाट जिले में अब 51वाँ मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसके बाद 11 और आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे।

नक्सल उन्मूलन और क्षेत्र विकास के लिए जो जरूरत होगी पूरी की जाएगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में इन बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत सरकार के मिशन 2026 को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। नक्सल उन्मूलन और नक्सल क्षेत्र विकास के लिए जो जरूरत होगी पूरा किया जाएगा। अभी यह 246 किमी.की सड़क बनाई गई है और 120 किमी की सड़क निर्माणाधीन है। साथ ही 27 हाई

लेवल ब्रीज बन चुके हैं और नेटवर्क का कार्य तेज गति से बढ़ रहा है। यहां 34 नेटवर्क के टॉवर 4 जी के साथ प्रारम्भ हुए हैं। इसके अलावा बालाघाट में ही पूरे देश में पीएम जनमन योजना में बनने वाली पहली सड़क भी बनकर तैयार हुई है। वहीं 260 बैगा बसाहटों में बिना छत वाले मकानों को पक्की छत देने का कार्य तेजी से हो रहा है।

भी बालाघाट में नक्सल गतिविधियों पर नकेल कसने में सफलता मिली है। सीधी बात है आंतरिक सुरक्षा में जवान मुंहतोड़

जवाब दे रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने बालाघाट जिले के लांजी में 64 सुरक्षा जवानों के क्रम से पूर्व पदोन्नति कार्यक्रम में कहीं।

नक्सलियों सरेंडर करो, नहीं तो मार दिए जाओगे

लाल सलाम वालों को जीने का हक नहीं; 64 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नक्सलियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि सरेंडर हो जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। उन्होंने कहा कि अन्याय करने वाले, अनावश्यक रूप से लोगों का खून बहाने वाले और लाल सलाम करने वालों को जीने का हक नहीं देंगे। आपको इस धरती पर जीने का हक नहीं देने वाले।



- सीएम ने नक्सलियों को लेकर कहा कि हमारे भोले-भाले लोगों के बीच आप भ्रम फैलाते हो, झूठ बोलते हो। कारयाराना हरकत करते हो, ऐसे लोगों से निपटने में सरकार सक्षम है। पुलिस बल की मदद से समाज अब सामने खड़ा हो रहा है। जहां जरूरी होगा, वहां कार्यक्रम करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सरकार अभियान चला रही है। बता दें कि सीएम डॉ. मोहन यादव सोमवार को बालाघाट में क्रम-से-पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में शामिल हुए।

प्राचीन राममंदिर परिसर में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया लोकार्पण

300 वर्ष पुरानी बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य का हुआ लोकार्पण

बालाघाट । राष्ट्रबाण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले के विकासखंड लांजी में प्राचीन राममंदिर परिसर स्थित लगभग 300 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा-अर्चना कर बावड़ी परिसर की ऐतिहासिक महत्ता को नमन किया तथा परिसर में पहुंचकर बावड़ी का अवलोकन भी किया। जिला प्रशासन द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत श्रमदान कर बावड़ी का जीर्णोद्धार कराया



गया है।

उल्लेखनीय है कि यह ऐतिहासिक बावड़ी 17 वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य गोंड शासक श्री हड़्रेसिंह वल्के द्वारा

निर्मित कराई गई थी। पत्थरों की सीढ़ियों और 12 इंची ईंटों से निर्मित यह बावड़ी लंबे समय से राममंदिर से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों तथा पूर्व में किले के



सैनिकों और श्रद्धालुओं के पेयजल का प्रमुख स्रोत रही है। इस दौरान सांसद श्रीमती भारती पारधी, लांजी विधायक श्री राजकुमार करहि, कटंगी विधायक श्री गौरव पारधी,

कलेक्टर श्री मृणाल मोना, एसपी श्री नगेन्द्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

● देश के अग्रणी राज्यों में

एक है मध्यप्रदेश - मंत्री

उदय प्रताप सिंह

परिवहन व स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह अपने उद्बोधन में कहा कि मप्र सरकार की मंशा न केवल सरकारी कर्मचारियों को लाभ प्रदाय करना है अपितु आदिवासी अंचल तक भी शासन की योजनाओं का लाभ प्रदाय करवाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में आज मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक कि श्रेणी में उभर रहा है।

● सुरक्षा में बहुत बड़ी

समस्या है नक्सलवाद -

पुलिस महानिदेशक

कार्यक्रम के दौरान मप्र पुलिस के महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। जिसका उन्मूलन मार्च 2026 तक करने का केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित साह का संकल्प है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में एंटी नक्सल ऑपरेशन में तीव्र गति आयी है।

● नक्सलवाद के ख़ात्मे

को लेकर कृत संकल्पित

है बालाघाट - एसपी सिंह

कार्यक्रम के दौरान एसपी नगेन्द्र सिंह ने स्वागत संबोधन में कहा कि जिले की हॉक फोर्स, सीआरपीएफ और जिला बल सभी टीमों कृत संकल्प होकर मिशन 2026 के नक्सलवाद के समूल ख़ात्मे को लेकर संकल्पित होकर कार्य रही है। एसपी श्री सिंह ने कहा कि जवान जिन परिस्थितियों में नक्सलियों के साथ लोहा लेते है उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है।



पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार में जनता प्रशासन को अवगत कराएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कुओं, बावड़ी व तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए कोई भी नागरिक प्रशासन को अवगत करा सकता है। कार्यक्रम के दौरान सांसद श्रीमती भारती पारधी, लांजी विधायक राजकुमार करहि, कटंगी विधायक गौरव पारधी, परसवाड़ा विधायक मधुभगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे, नपा अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा ताराचंद कालबेले पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, रमेश भट्टे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्लार मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों में आईजी संजय सिंह, एसपी विजय डावर, एसपी नक्सल आदर्श कांत, कलेक्टर मृणाल मोना, जिप सीईओ अभिषेक सराफ, एडीएम जीएस धुर्वे, एसडीएम बालाघाट गोपाल सोनी, एसडीएम लांजी कमलचंद सिंहसार, एसडीएम किरनापुर श्री कार्तिकेय व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही।



बिना सुई चुभाए शुगर लेवल का पता चलेगा

बालाघाट की छात्रा ने बनाई अनोखी डिवाइस; इंसेक्ट डिटेक्टर बताएगा सब्जी में कीड़े हैं या नहीं

बालाघाट । राष्ट्रबाण

शुगर की जांच के लिए खून की कुछ बूंदें चाहिए होती हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में यह जरूरी नहीं होगी। मरीज को सिर्फ एक डिवाइस में फूंक मार कर पता चल जाएगा कि शरीर में शुगर लेवल क्या है? एमपी के बालाघाट की छात्रा ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, जो बिना सुई चुभाए सिर्फ सांस के जरिए शरीर में शुगर लेवल बताती है। छात्रा ने इसका नाम शुगर ब्रीथ एसीटोन 3.0 रखा है।

शुगर ब्रीथ एसीटोन 3.0 कैसे काम करती है?

बालाघाट के जेएसटी पीजी कॉलेज की स्टूडेंट अभिलाषा की यह डिवाइस सांस में मौजूद किटोन बॉडीज का विश्लेषण करती है, जो शुगर लेवल बढ़ने पर शरीर में अधिक मात्रा में बनने लगती है। मरीज जब डिवाइस में फूंकता है, तो यह तीन श्रेणियों में रीडिंग दिखाती है। लो : शुगर लेवल कम है। मॉडरेट : शुगर लेवल सामान्य है।

हाई : शुगर लेवल अधिक है, डायबिटीज का संकेत हो सकता है। अभिलाषा का कहना है कि यह डिवाइस खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें सुई से डर लगता है, जिसके कारण वे ब्लड शुगर की नियमित जांच नहीं कर पाते। यही लापरवाही अक्सर बीमारी को गंभीर बना देती है।

दरअसल, भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सुजन-2025 कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें 1627 नवाचारों में से चुने गए टॉप 150 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगी है। एक डिवाइस तो ऐसी है

जो फल-सब्जियों में छिपे कीड़ों और खतरनाक रसायनों की पहचान करती है। इसके अलावा दृष्टिहीनों की राह आसान बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक छड़ी तैयार की है जो आंखों की तरह मार्गदर्शन करती है।

अतिक्रमण हटने के बाद पुनः कब्जा

प्रशासन को सख्ती की जरूरत, बराबर हो रहा अतिक्रमण से बिगड़ती है यातायात और शहर की सुंदरता

सिवनी। राष्ट्रबाण

जिला मुख्यालय स्थित शासकीय जमीन से दो माह पूर्व ही प्रशासन ने मुहिम चलाकर अतिक्रमण हटया कर रोड चौड़ीकरण करने का कार्य किया जा रहा था। इसके बाद प्रशासन ने जबलपुर रोड से लेकर छिंदवाड़ा चौक तक अतिक्रमण वाली जगह को चिन्हित कर निशान लगाया था। लेकिन देखने में आया कि मुहिम वाली कार्यवाही सिर्फ चुनिंदा जगह पर ही गई थी। बाकी जगह अतिक्रमण हटाने की औपचारिकता पूरी की गई थी।

गौरतलब है कि मार्च महीने में कलेक्टर के निर्देश पर शहर के मुख्य मार्ग जबलपुर नागपुर रोड पर मुख्यतः से अतिक्रमण मुहिम चलाई गई थी। इसमें शासकीय निस्तार भूमि से लेकर अन्य



शासकीय मदो की भूमि से अतिक्रमण हटया गया था। इससे नगरवासी ने राहत महसूस की थी। इसके बाद लगातार कार्यवाही नहीं होने से उक्त स्थानों पर फिर से लोगों ने द्वारा कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे शासकीय जमीन का रकबा दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इस कारण नगरवासी अभी भी परेशानी का सामना करना पड़

रहा है।

नोटिस तक सीमित रहता है अतिक्रमण

अतिक्रमण को देखते हुए प्रशासन के ऊपर एक कहावत सटीक बैठती है -अवसर गरीब ही पिस्ता है- वैसे ही जिला प्रशासन ने किया। गरीबों का आशियाना पल भर में ही मिटा दिया और वहीं पावरफुल व्यक्तियों के सामने सिर

मस्तक करते हुए उनकी बातों का मान रखते हुए कुछ वक्त दे दिया था। जिसका फायदा वह आज दिनांक तक उठा रहे हैं। देखने की यह बात है कि गरीबों पर प्रशासन कार्रवाई तत्काल प्रभाव से करता है और वही पावरफुल व्यक्ति के सामने प्रशासन मौन होकर कुछ देर में ही नौ दो ग्यारह हो जाता है फिर कछुए की चाल में कार्यवाही को

डाल देता है। जबकि कुछ जगह में तो कागजों में ही मुहिम चलाकर अतिक्रमण हटा दिया गया है। इसके बाद लंबे वक्त तक पुनः अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं होने से फिर से लोगों ने अपना-अपना कब्जा पुनः स्थापित कर लिया है।

गौरतलब यह है कि जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी जैसे कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी एवं अन्य अधिकारी की गाड़ियां प्रतिदिन इन्हीं रास्ते से अपने दफ्तर आती जाती हैं। उसके बावजूद भी उनकी आंखों में कौनसी पट्टी बंधी हुई है यह तो वही बता सकते हैं। सर्किट हाउस चौक से जनपद पंचायत सिवनी, बस स्टैंड होते हुए छिंदवाड़ा चौक तक पुनः व्यापारियों ने अपनी दुकान सजा रखी है।

सिकल सेल मरीजों के लिए दो दिवसीय टीकाकरण कार्यक्रम

जिला चिकित्सालय और सभी सीएचसी पर 14 और 15 मई को लगेगा कैंप



बैतूल। राष्ट्रबाण

जिला चिकित्सालय में नेशनल सिकल सेल कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 20 वर्ष के चिन्हित सिकल सेल रोगियों के लिए 14 और 15 मई 2025 को विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के मरीजों का टीकाकरण जिला चिकित्सालय के एम.सी.एच. भवन में स्थित टीकाकरण कक्ष में किया जाएगा। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों का टीकाकरण उनके विकासखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होगा।

सिकल सेल कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ अंकिता सिते ने बताया कि कैंप को लेकर सीएमएचओ डॉ राजेश परिहार ने आदेश जारी किया है कि सिकल सेल मरीजों के टीकाकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाए और सभी मरीजों का टीकाकरण किया जाए। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन डॉ जगदीश घोर शिविर का आयोजन कर रहे हैं।

डॉ सिते ने बताया कि शिविर में सिकल सेल रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण और रक्त परीक्षण भी किया

जाएगा। मरीजों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर डिस्पेंसिलिट्री प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। टीकाकरण के बाद मरीजों को फॉलोअप कार्ड जारी किया जाएगा।

मरीजों के परिजनों को निर्देश दिए हैं कि वे शिविर में सिकलसेल रिपोर्ट (एच.पी.एल.सी.) की छायाप्रति,आधार कार्ड की छायाप्रति,समग्र आईडी की छायाप्रति,पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लेकर आए। शिविर में उपस्थित होने वाले मरीजों से अपील की गई है कि वे अपने विकासखण्ड के चिकित्सा अधिकारी या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से संपर्क कर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। प्रयास किया जा रहा है सिकल सेल मरीजों की 100 प्रतिशत उपस्थिति रहे ताकि अधिक से अधिक सिकल सेल रोगियों को इस लाभकारी कार्यक्रम का लाभ मिल सके।

मवेशियों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार



सिवनी। राष्ट्रबाण

सिवनी जिले में छपारा पुलिस ने सोमवार को एक पिकअप वाहन से 3 बैलों को बरामद किया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर 12 मई को पुलिस टीम ने जबलपुर बायपास छपारा चौराहे पर नाकाबंदी की। पिकअप वाहन (क्रमांक ख्ब 18 ब्र 2029) को

रोकने का प्रयास किया गया। चालक ने वाहन को खतरनाक तरीके से बगाने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर टाटा मोटर्स के पास वाहन को रोका। जांच में पाया गया कि वाहन में 3 बैलों को क्रूरतापूर्वक रस्सियों से बांधकर भरा गया था। इन्हें लखनादौन से नागपुर के कल्लखाने ले जाया जा रहा था।

आरोपी नरसिंहपुर के रहने वाले: गिरफ्तार राज राय (23 वर्ष) और खेमचंद गोड (20 वर्ष) दोनों नरसिंहपुर जिले के गाड़वाड़ा खेड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस ने वाहन और मवेशियों को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

भारतीय पत्रकारिता जगत ने आज अपना एक स्तंभ खो दिया

बैतूल। राष्ट्रबाण

पत्रकारिता जगत के लिए मंगलवार, 13 मई 2025 का दिन अपूरणीय क्षति लेकर आया। देश के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पत्रकार डॉ. के. विक्रम राव का प्रातः लखनऊ में निधन हो गया। सांस संबंधी तकलीफ के चलते उन्हें सुबह लखनऊ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉ. के. विक्रम राव दशकों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उनकी लेखनी निर्भीक, स्पष्टवादिता और सिद्धांतों पर आधारित रही। उन्होंने देश भर में पत्रकारों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की और भारतीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएँ दीं।



डॉ. के. विक्रम राव।

उनके निधन का समाचार मिलते ही पूरे देश के पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई। बैतूल जिला मुख्यालय के मीडिया सेंटर में मंगलवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें जिले के पत्रकार, समाजसेवी और बुद्धिजीवी उपस्थित हुए। इस अवसर पर बैतूल जिले के वरिष्ठ पत्रकार रामकिशोर पवार, जो कि बीते 38 वर्षों से डॉ. राव के संपर्क में रहे, उन्होंने कहा कि पत्रकारिता

एक स्तंभ खो दिया

का एक मजबूत स्तंभ आज हमसे विदा हो गया। उन्होंने बताया कि डॉ. राव ने हमेशा पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से उठाया और उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाई।

डॉ. के. विक्रम राव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए 703, पैलेस कोर्ट अपार्टमेंट, निकट कांग्रेस कार्यालय, मॉल एवेन्यू, लखनऊ स्थित उनके निवास पर रखा गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंच रहे हैं। भारतीय पत्रकारिता के इस युगपुरुष को नमन करते हुए जिले के पत्रकारों ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ईश्वर से प्रार्थना की गई कि वे दिवंगत आत्मा को शांति दें और शोकाकुल परिवार को यह वज्राघात सहने की शक्ति प्रदान करें।

लालबर्रा क्षेत्र भर में जेसीबी से बेखौफ होकर अवैध उत्खनन व परिवहन

जिम्मेदार प्रशासन हुआ बेलगाम

मजदूरों को काम देना छोड़, जेसीबी को दिया जा रहा काम



पांढरवानी गार्डन तालाब में 3 जेसीबी से खनन कर मिट्टी का व्यवसायिक उपयोग

लालबर्रा। राष्ट्रबाण

बालाघाट जिले के लालबर्रा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत चारो तरफ विभिन्न पंचायत में मजदूरों की जगह बेखौफ होकर जेसीबी से अवैध उत्खनन कर दर्जनों ट्रैक्टर से परिवहन कर मिट्टी बेची जा रही है। नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांढरवानी (लालबर्रा) में पांढरवानी रोड में बने गार्डन तालाब में 3 जेसीबी से खनन कर दर्जनों ट्रैक्टर से परिवहन कर मिट्टी का व्यवसायिक उपयोग कर नगर में विभिन्न स्थानों पर प्लांटिंग में ग्राम पंचायत पांढरवानी द्वारा मिट्टी बेची जा रही है, 8 मई गुरुवार को 1 जेसीबी, शुक्रवार को 2 जेसीबी से तो शनिवार को 3 जेसीबी के माध्यम से नियम विरुद्ध मजदूरों को काम देना छोड़ उनके पेट पर लात मारकर जेसीबी मालिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जेसीबी को तालाब में खुदाई के लिए काम नहीं दिया जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन मजदूरों को उनके हक का मजदूरी का काम नहीं दिया जाएगा तो जरूर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ग्राम पंचायत पांढरवानी सरपंच द्वारा जिला पंचायत से शासकीय तालाब को गहरीकरण करने के लिए स्वीकृति ली गई है। स्वीकृति किस मद से, किन्तनी लागत से इसका साईन बोर्ड निर्माण कार्य स्थल पर नहीं लगाया गया है, आम जनता से जानकारी छुपाई जा रही है जिससे कि भ्रष्टाचार होने का अदेशा लग रहा है। स्थानीय जनपद स्तर से कोई स्वीकृति नहीं है।

मछुआरा समिति लालबर्रा के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा इस शासकीय तालाब को 10 वर्ष के लिए 2024 से 2034 तक मछली पालन व्यवसाय के लिए किराए पर लिया गया है। जहां मछुआरा समिति ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष लगभग एक से डेढ़ लाख रुपये का मछली बीच तालाब में डाला था जिसकी फसल अब तैयार हो चुकी थी जहां से वह कुछ मछलियां बेच चुके हैं लेकिन ओर बहुत मछलियां तालाब में बाकी थी लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा तालाब की मेड़ पार को एक स्थान से काट दिया गया है जिससे पानी बह गया, जिसके कारण मछुआरा समिति बता रही है कि उन्हें लगभग 5 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है, इशर मछुआरा समिति को लाखों का नुकसान तो मजदूरों के हक की राशि जेसीबी मालिक को मिलेगी। मजदूरों को काम दिलाकर उनकी लाभ पहुंचाना शासन -प्रशासन की मंशा रहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

लालबर्रा क्षेत्र में चारों तरफ अनेक पंचायत व अन्य स्थानों पर जेसीबी मशीन के माध्यम से अवैध रूप से खनन कर बिना व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन वाले मतलब कृषि कार्य वाले ट्रैक्टरों से

पंचायत के संचालन के लिए वरदान साबित हो रही मनरेगा योजना



विदित हो कि पंचायत के मैनेजमेंट व पंचों को साधने के लिए इन दिनों मनरेगा योजना पंचायत के लिए वरदान साबित हो रही है। देखने में आ रहा है कि पंचायत द्वारा अपने निजी खर्च, पंचायत में लगने वाले चाय नाश्ता, सरपंच सचिव रोजगार सहायक के अपने निजी चाय पान का खर्च भी मनरेगा योजना से दुकानदार के नाम से हाजिरी भरकर मैनेज किया जा रहा है। इसलिए यहां यह कहना लाजमी नहीं होगा कि मनरेगा योजना अंतर्गत कच्ची नाली व नालापथोपचार के भरोसे पंचायत का मैनेजमेंट पंचों को साधने व अपने अन्य निजी खर्च के लिए

मनरेगा योजना वरदान साबित हो रही है। अधिकारियों के संरक्षण में मनरेगा योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों में फर्जी हाजिरी, जेसीबी का उपयोग बेखौफ होकर किया जा रहा है। अब यह देखना बाकी होगा कि माह म ई और जून में मनरेगा योजना में अनियमितता, भ्रष्टाचार व मनमानी के कितने और मामले जागरूक ग्रामीणों के माध्यम से अखबारों की सुर्खियां बटोरेंगे। जिम्मेदार अधिकारियों से जानकारी लेने पर मीडिया को गुमराह करते हैं और गोलमोल जानकारी देकर जिम्मेदार बचते हैं। सब कुछ जानकर भी बनते हैं अनजान।

परिवहन कर व्यावसायिक उपयोग कर प्लांटिंग में या अन्य स्थान पर मिट्टी बेची जा रही है। कई बिना नंबर के ट्रैक्टर सड़क पर फरटें भरते हुए दौड़ रहे हैं इनमें कई चालक के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होंगे, यदि इन तेज रफ्तार सरपट दौड़ रहे ट्रैक्टरों से कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उस मिट्टी की खुदाई जेसीबी से की जा रही है जिसका पैसा शासन मजदूरों के नाम पर देगी और इस मिट्टी को ग्राम पंचायत सरपंच सचिव रोजगार सहायक व्यवसायिक उपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति को प्लांटिंग के स्थान पर या अन्य जगह मिट्टी को बेचकर मालामाल हो रहे हैं।

पंचायत में निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदार सरपंचों को 10 से 15ब तक कमीशन देते हैं। ऐसे में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

क्षेत्र की अधिकांश पंचायत में सरपंच अपनी मनमानी कर रहे हैं। जनपद पंचायत व जिला पंचायत की सांठांट से अधिकांश ठेकेदार ग्राम पंचायत में नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं और बेहद घटिया स्तर का कार्य शासन प्रशासन की सांठांट से कर रहे हैं। सरपंच सचिव रोजगार सहायक, उपयंत्री एसडीओ सीईओ संबंधित बाबू से सांठांट का कर ठेकेदार इन्हें कमीशन देकर सरेआम गुणवत्ता को ताक में रखकर काम कर रहे हैं। खुलेआम चल रही जेसीबी जिम्मेदार बने मूक दर्शक, मजदूरों के हक पर डाका डाल कर पंचायतें जेसीबी से करवा रही काम।

अधिकांश ग्राम पंचायतों की तो मनरेगा योजना में लूट और भ्रष्टाचार रकने का नाम ही नहीं ले

रहा, परंतु इन योजनाओं का लाभ कुछ अधिकारी और उनसे जुड़े हुए संबंधित लोगों के कारण गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि लालबर्रा जनपद क्षेत्र में सरपंचों की मनमानी और जिम्मेदार अधिकारियों की आपसी सांठांट से मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। जहां सरपंच सचिव रोजगार सहायक, उपयंत्री शासन के नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते हुए मनरेगा व अन्य योजनाओं के तहत किए जाने वाले कार्य गांव के मजदूरों से कराने की बजाय जेसीबी मशीन लगाकर बेखौफ होकर धड़ल्ले से करवाया जा रहा है।

जनपद क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में इन दिनों मनरेगा योजना अंतर्गत सुदूर सड़क, तालाब निर्माण (परकुलेशन टैंक), पुलिया निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्य प्रारंभ है, जहां गांव के सरपंच सचिव रोजगार सहायक व संबंधित उपयंत्री द्वारा मनरेगा के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्य स्थानीय ग्रामीण जाँब कार्ड धारक मजदूरों से न कराते हुए निर्माण कार्य को जेसीबी मशीनों से कराया जा रहा है, जबकि शासन के नियम के मुताबिक निर्माण लागत का 60 फ़ीसदी कार्य मनरेगा जाँब कार्ड धारी मजदूरों से कराना आवश्यक होता है, लेकिन लालबर्रा जनपद की अधिकांश पंचायतों में मनरेगा निर्माण कार्य जो लाखों रुपए की लागत से किया जा रहा है। मजदूरों के हक पर डाका डालकर मशीनों से कार्य करते हुए अपने चित परिचित एवं सगे संबंधियों के जाँब कार्ड में फर्जी तरीके से हाजिरी डालकर लाखों रुपयों का बंदरबांट कर रहे हैं।